SEM-1, BY-Dr. S.B. choudhary

Education of Rural Population. TOPIC, SC-102 Date 21-06-21

ग्रामीण जनता की शिक्षा :- सामान्य जन के कल्याण के लिए सुखी जीवन बिताने के लिए, अच्छा नागरिक बनाने के लिए, जनतन्त्र को सुरक्षित रखने के लिए, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता के लिए, देश की आर्थिक समृद्धि के लिए निरक्षरता उन्मूलन आवश्यक है। साक्षरता आर्थिक वृद्धि में भी सहायक है, क्योंकि साक्षर मनुष्य उत्पादन में सहायता करता है। निरक्षरता के उन्मूलन का प्रयास स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही चल रहा है किन्तु विगत कुछ वर्षों में इस प्रयास में तेजी आई है और प्रयास बहुत अधिक सीमा तक सार्थक सिद्ध हुए हैं।

निरक्षरता मानव जीवन का अभिशाप है। सन् 1991 में भारत में साक्षरता प्रतिशत 52.21% था इसमें 13.17% की वृद्धि हुई है और सन् 2001 में साक्षरता प्रतिशत 65.38% हो गया। पुरुषों में सन् 1991 में यह प्रतिशत 64.1 था, सन् 2001 में यह 75.8% हो गया। इन निरक्षरों में भी हमें साक्षरता का प्रसार करना है।

1988

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन :- सन् 1988 में देश पूर्ण साक्षरता प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई और लक्ष्य रखा गया कि सन् 2005 तक निरक्षरता का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया जाए। इसका उद्देश्य ऐसे निरक्षरों को साक्षर बनाना है, जो अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी आयु 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच है। अनौपचारिक शिक्षा से वंचित 9-14 आयु वर्ग के बच्चे भी शामिल कर लिए जाते हैं।

6-14 सन् 1989 में अर्नाकुलम जिले में पूर्ण साक्षरता ने इस मिशन के लिए आदर्श उपस्थित किया। इस समय देश में 561 जिलों में इस मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रम चल रहे हैं और लगभग नौ करोड़ लोगों को साक्षर बनाया गया है। इनमें से 166 जिलों में पूर्ण साक्षरता आंदोलन चलाया है, 290 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया है और 105 जिलों को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है।

इस प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने भारत में निरक्षरता उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया। यह आशा की जाती है कि सन् 20 या उसके दो एक वर्ष बाद भारत में निरक्षरता का पूर्णतया उन्मूलन हो जायेगा।